केंद्रीय सलाहकार समिति की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त

स्थान :होटल अशोक, नई दिल्ली

दिनांक और समय : 22 फरवरी, 2011, प्रातः 11.00 बजे

प्रतिभागियों की सूची : अनुलग्नक–1

22.02.2011 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की तीसरी बैठक।

श्री वी.एन. गौड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई और सीएसी के अध्यक्ष, ने सीएसी की तीसरी बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने सदस्यों को सीएसी की दूसरी बैठक के बाद वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की गतिविधियों के बारे में बताया। मसौदा नियमों को अधिसूचित किया गया है और वे लगभग अंतिम चरण में हैं। एफएसएसएआई ने प्राप्त की गई हर टिप्पणी पर काम किया है और जहां भी जरूरी हुआ आवश्यक परिवर्तनों को शामिल किया गया है। मसौदे का विनियम सं. 603 जिसमें दूध और दूध उत्पाद तथा कीटनाशकों से संबंधित दो नियम शामिल हैं, अंतिम चरण में हैं। इन नियमों की अनुमोदन प्रक्रिया अपने स्थान पर है और समय पर, इन्हें अधिसूचित किया जाएगा। मसौदा नियमों को शीघ्र ही अंतिम रूप में अधिसूचित किए जाने की संभावना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अधिनियम के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निभाई जाएगी।

इस बैठक की मुख्य कार्यसूची कर्मचारियों, प्रयोगशालाओं और बुनियादी सुविधाओं, आदि के संदर्भ में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की स्थिति की समीक्षा होगी।

सीईओ ने सूचित किया कि एफएसएसएआई ने पहले से ही पांच प्रमुख बंदरगाहों पर आयातित खाद्य पदार्थों के नियंत्रण को लागू करना शुरू कर दिया है। कुछ प्रारंभिक अड़चनों के बाद प्रक्रिया को जेएनपीटी, मुंबई, कोलकाता, हल्दिया और चेन्नई के इन सभी बंदरगाहों में सुव्यवस्थित कर लिया गया है। एफएसएसएआई ने इन बंदरगाहों में से प्रत्येक में अधिकृत अधिकारियों को नियुक्त और अधिसूचित किया है। दूसरे चरण में एफएसएसएआई अन्य प्रमुख समुद्री बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर, आयातित खाद्य को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। प्रशिक्षित जनशक्ति की सीमाओं को देखते हुए इन विशेषज्ञ कार्यों का निर्वहन एक कठिन कार्य साबित हो रहा है।

प्रशासनिक पक्ष पर, एफएसएसएआई ने 533 अतिरिक्त पदों के लिए अनुरोध किया था, जबकि सरकार ने 355 पदों को मंजूरी दी है, जिनमें वैज्ञानिक, प्रवर्तन, निगरानी और प्रशासन के कर्मी भी शामिल हैं। मसौदा भर्ती नियम प्रारंभिक चरण में हैं

उन्होंने पर्चों, पुस्तिकाएं, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से विज्ञापन जैसे प्रासंगिक चैनलों के माध्यम से अलग–अलग भाषाओं में खाद्य सुरक्षा के संदेश का संचार करने के महत्व पर बल दिया, जिससे जनता, खाद्य व्यापार संचालकों और अन्य हितधारकों के बीच खाद्य सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने एक हेल्पलाइन प्रणाली स्थापित करने का भी सुझाव दिया जो लोक शिकायत या शिकायत प्रकोष्ठ के रूप में भी कार्य कर सकती है।

उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार ने एक 'व्हिसल ब्लोअर' योजना की घोषणा की है, जो अभी प्रारंभिक चरण में है। भोजन से संबंधित मिलावट के मामलों और अन्य कदाचार, जिनके लिए अधिनियम में प्रावधान मौजूद है, की रिपोर्ट करने वाले लोगों को पुरस्कार देकर. 'व्हिसल ब्लोअर' तंत्र को प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से भोजन के नमूनों के परीक्षण के लिए ईओआई मांगा गया है, जो खाद्य निगरानी प्रणाली को मजबूत करने और निगरानी के मामलों के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए भी पीएफए प्रयोगशालाओं के साथ काम करेंगी।

कार्यसूची 1: सीएसी की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

सीएसी ने 22 अक्टूबर, 2010 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि की।

कार्यसूची 2: पीएफए से एफएसएस अधिनियम के लिए तैयारियों की समीक्षा:

कार्यसूची 3: लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली:

कार्यसूची 4: एफएसएसएआई द्वारा प्रस्तावित संरचना की तुलना में राज्यों द्वारा उठाए कए कदम:

कार्यसूची 5: सार्वजनिक खाद्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए राज्यों द्वारा कार्य योजना:

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि चूंकि कार्यसूची के मद सं. 1–5 आपस में जुड़े हुए हैं और प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए की जाने वाली कार्रवाई/तैयारियों की स्थिति के संबंध में हैं, इसलिए इन सभी को एक साथ लिया जा सकता है। प्रतिनिधियों से कार्यसूची 2, 3, 4 और 5 पर टिप्पणी और सुझाव, यदि कोई हो, तो देने का अनुरोध किया गया। बैठक के दौरान प्रस्तुत अनुसार प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशो द्वारा की तैयारियों/की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है।

विभिन्न राज्यों से टिप्पणी:

1. **मणिपुर:**

मणिपुर के प्रतिनिधि ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने प्रशिक्षण में भाग लिया और राज्य के अन्य अभिहित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहां 9 जिले हैं और बराबर संख्या में खाद्य निरीक्षक उपलब्ध हैं। कर्मियों और धन की कमी है। राज्य में दो प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। सीमावर्ती जिलों में दो और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की आवश्यकता है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस तरह की गतिविधियों के लिए धन राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा क्योंकि अंततः कानून का प्रवर्तन राज्यों की जिम्मेदारी है। लेकिन राज्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन और मान्यता के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने आगे जानकारी दी कि एफएसएसएआई ने योजना आयोग से बातचीत शुरू की है और उनसे अतिरिक्त धन आवंटित करने का अनुरोध भी किया है जो अगले वित्त वर्ष में राज्यों को दिया जा सकता है।

2. गुजरातः

प्रतिनिधि ने सीएसी को सूचित किया कि राज्य एफएसएस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए तैयार है। गुजरात के विभिन्न भागों में मौजूद 6 प्रयोगशालाएं भी एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय निर्धारित किया गया है और यह मार्च के अंत तक पूरा हो जाएगा। खाद्य निरीक्षकों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। राज्य में चरणबद्ध तरीके से अच्छे विनिर्माण आचरण, अच्छे हैंडलिंग आचरण, अच्छे प्रयोगशाला आचरणों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

सीईओ, एफएसएसएआई ने गुजरात के कार्यों की सराहना की।

3. गोवाः

राज्य के प्रतिनिधि ने सूचित किया स्थानीय गृह विज्ञान कॉलेज की मदद से, राज्य में सड़क पर बिक्री करने वालों को अच्छे विनिर्माण आचरण पर प्रशिक्षण दिया गया। इससे विक्रेताओं के साथ–साथ उपभोक्ताओं में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता में सुधार हुआ है। राज्य में केवल एक प्रयोगशाला है और यह एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत है। न्यायनिर्णयन अधिकारी के लिए नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है और खाद्य निरीक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो चुका है।

4. केरलः

एनआरएचएम की वित्तीय सहायता से खाद्य सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय पूरी तरह कार्यात्मक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का क्षमता निर्माण कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अभिहित अधिकारियों का प्रशिक्षण मार्च तक पूरा हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और अभिहित अधिकारियों के लिए अधिसूचना अंतिम चरण में हैं। सभी 14 जिलों में खाद्य व्यापार संचालकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्यूसीआई ने 3 में से 2 प्रयोगशालाओं का दौरा किया और उनके उन्नयन की प्रक्रिया चल रही है।

5. महाराष्ट्रः

राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अधिसूचित किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अभिहित अधिकारी, आदेश अंतिम चरण में हैं। राज्य में दो प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं। राज्य में कर्मचारियों की कुछ कमी है। राज्य खाद्य आयुक्त ने एफएसएसएआई से प्रयोगशाला कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाने में राज्य की मदद करने के लिए अनुरोध किया क्योंकि धन की कमी की वजह से, प्रगति बहुत धीमी है। खाद्य निरीक्षक का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है।

इस के जवाब में, सीईओ एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया कि प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि वर्ष 2010 के लिए खाद्य विश्लेषक परीक्षा पूरी हो चुकी है जल्द हीअगली ` परीक्षा के बारे में सूचना एफएसएसएआई की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

6. उत्तराखंडः

खाद्य सुरक्षा आयुक्त और अन्य अधिकारियों की भर्ती और अधिसूचना की प्रक्रिया चल रही है।

7. दिल्लीः

दिल्ली ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्त की है। राज्य एफएसएस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को सक्रिय रूप से शामिल करने की कोशिश कर रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य निरीक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में 27 उप प्रभागों के एसडीएम को अधिसूचित किया गया है और एलएचए तथा यह प्रणाली संतोषजनक ढंग से काम कर रही है। जलोदर की घटना के बाद यह परिवर्तन लाया गया है। अब, चूंकि पूर्ण कालिक एसडीएम को एफएसएस अधिनियम के तहत अभिहित अधिकारी के रूप में नियुक्त करना संभव नहीं होगा इसलिए अभिहित अधिकारी पर पर्यवेक्षण बनाए रखने में जिला प्रशासन को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि खाद्य सुरक्षा आयुक्त के लिए सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना संभव नहीं है।

8. हिमाचल प्रदेशः

राज्य ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त की पहचान की है। अभिहित अधिकारियों का प्रशिक्षण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। राज्य में कर्मियों और धन की कमी है। शिमला में स्थित एक प्रयोगशाला के लिए अंतराल विश्लेषण किया जा रहा है।

9. आंध्र प्रदेशः

राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त किया गया है। अभिहित अधिकारियों और अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती के लिए अधिसूचना की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ एक प्रयोगशाला है जिसमें जीएलपी के अनुसार योग्य कर्मी और आवास है और यह एनएबीएल से मान्यता के लिए आवेदन करेगी।

राज्य ने उन्नयन के लिए विशाखापट्नम और गुंटूर में दो और प्रयोगशालाओं की पहचान की है। खाद्य विश्लेषक और न्यायनिर्णयन अधिकारी के लिए नियुक्ति और अधिसूचना की प्रक्रिया चल रही है। हैदराबाद और विजयवाड़ा में दो खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिए सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। एफएसएस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिलावट के मामलों में जानकारी देने वाले 'व्हिसल ब्लोअर' के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू करने का फैसला किया गया था। क्षमता निर्माण परियोजना के तहत, एचसीएल ने राज्य मुख्यालय के साथ–साथ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को इकाई की निगरानी के लिए जिला कार्यालयों से डेटा के ऑनलाइन प्रसारण के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया था।

10. कर्नाटकः

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त अब खाद्य सुरक्षा के आयुक्त हैं। राज्य में मौजूद चार प्रयोगशालाएं राज्य स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की मदद से उन्नयन की प्रक्रिया के तहत हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अधिसूचना प्रक्रिया के तहत है और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था। सात अभिहित अधिकारियों को भी प्रशिक्षण मिला है। न्यायनिर्णयन अधिकारी की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और विशेष अदालतों के गठन का प्रस्ताव विधि विभाग में लंबित है।

11. मिजोरमः

खाद्य सुरक्षा आयुक्त की अधिसूचना प्रक्रिया के अंतर्गत है। खाद्य सुरक्षा के विषय पर राज्य भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी। अभिहित अधिकारी और कुछ खाद्य व्यापार संचालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो गया है। राज्य की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जुड़ी होने की वजह से खाद्य पदार्थ के नमूने की विस्तारित जाँच की जानी है।

सीईओ, एफएसएसएआई ने राज्य से तुरंत खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया।

12. छत्तीसगढ़ः

राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अधिसूचित किया है। अन्य अधिकारियों के लिए अधिसूचना की प्रक्रिया चल रही है। कर्मियों की कमी है इसलिए चिकित्सा अधिकारियों (एफएसओं) को एक महीने का प्रशिक्षण दिया गया था।

13. सिक्किमः

राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अधिसूचित किया गया है। कर्मचारियों और कोष की कमी है इसलिए राज्य एक उपयुक्त प्रयोगशाला नहीं है। नमूने गुवाहाटी प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं।

14. तमिलनाडुः

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो चुका है। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, जिला स्तर के अधिकारियों और न्यायनिर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए तैयार है। प्रयोगशालाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो गई है। राज्य छह प्रयोगशालाओं में से कम से कम दो प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने की कोशिश कर रहा है। विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रक्रिया चल रही है।

15. पश्चिम बंगालः

पूरी कर्मी संरचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के अधीन है। राज्य में लोक विश्लेषक को अधिसूचित किया गया है। विभिन्न अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम मई 2011 तक पूरा हो जाएगा।

16. उड़ीसाः

राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अधिसूचित किया गया है। उड़ीसा के सभी जिलों में खाद्य विश्लेषक हैं। लोक विश्लेषक मौजूद नहीं है।

17. जम्मू एवं कश्मीरः

पीएफए से एफएसएसए में संक्रमण किया जा रहा है। न्यायनिर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति राज्य के प्रशासन विभाग के पास लंबित है। श्रीनगर और जम्मू में स्थित दो प्रयोगशालाओं में पर्याप्त कर्मचारी हैं।

18.चंडीगढः

चंडीगढ़ में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का प्रवर्तन संतोषजनक है और उन्होंने प्रत्येक उप–खंड के लिए अभिहित अधिकारियों के रूप में तीन एसडीएम नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है।

19. पांडिचेरी:

राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अधिसूचित किया गया है। खाद्य विभाग को स्वास्थ्य से अलग करने की प्रक्रिया चल रही है। उपलब्ध प्रयोगशालाएं, उन्नयन की प्रक्रिया में हैं। अभिहित अधिकारियों का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है और खाद्य निरीक्षकों के लिए यह आयोजित किया जाना है।

20. त्रिपुरा:

राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अधिसूचित किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के पास एक प्रयोगशाला उपलब्ध है। खाद्य सुरक्षा में बुनियादी ज्ञान की कमी है और राज्य धीरे धीरे जानकारी में अंतराल को कम करने की कोशिश कर रहा है।

21. उत्तर प्रदेश:

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने घरों का दौरा किया और एक किट से खाद्य के नमूनों की जांच की गई। इससे जनता और विक्रेताओं में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है। विभाग के पास एक सक्रिय शिकायत प्रकोष्ठ है और प्राप्त शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जा रही है। वहां पाँच प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं, और उन्नयन की प्रक्रिया में हैं। नियमों की अधिसूचना के बाद शीघ्र ही अभिहित अधिकारियों, न्यायनिर्णयन अधिकारियों, अपीलीय ट्रिब्यूनल को अधिसूचित किया जाएगा।

राज्य के प्रतिनिधियों के कुछ सामान्य सुझाव थे। नियम और नियमन की अंतिम अधिसूचना के बाद कानून को लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने का सुझाव दिया गया था।

कुछ प्रतिनिधियों का सुझाव था कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि जैसे विभिन्न मीडिया के उपयोग का प्रयास किया जाना चाहिए और सुरक्षित भोजन और कानून के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और स्थानीय निकायों को भी शामिल किया जा सकता है।

इसी तर्ज पर, राज्यों और उपभोक्ता प्रतिनिधियों ने किसानों, उत्पादकों आदि के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया।

अध्यक्ष, एफएसएसएआई भी 12:40 बजे बैठक में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। अध्यक्ष ने एफएसएसए नियम/विनियम की अधिसूचना और राज्यों पर इसके प्रभाव के बीच लगने वाले समय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। श्री देसीकन ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशालय में असंतोष है क्योंकि कोई भी डॉक्टरों खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर प्रशिक्षित नहीं किया गया है। उन्होंने साल्मोनेला की समस्या, इडली और डोसा–बैटर में ई–कोलाई घटना जैसे कुछ अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष, एफएसएसएआई ने इस मुद्दे पर बताया कि एफएसएसएआई छह विभिन्न मंत्रालयों से लोगों को एकत्रित कर रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की वर्तमान में उपलब्ध लगभग 2000 कर्मचारियों की संख्या के साथ अधिनियम को लागू करना एक चुनौती होगी। खाद्य सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी खाद्य व्यापार संचालकों के स्तर पर टिकी हुई है। इस प्रयोजन के लिए, खाद्य व्यापार संचालकों को ज्ञान से सशक्त करना महत्वपूर्ण है ताकि उद्योग अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सके। प्रक्रिया में प्रति वर्ष,

खाद्य व्यापार संचालकों के परिसर में, कम से कम एक निरीक्षण करना शामिल है। हालांकि, 90 प्रतिशत खाद्य व्यापार संचालक प्रणाली से बाहर हैं। ऐसी स्थिति में केवल स्व–नियमन का तंत्र ही काम करेगा। भारत का एचएसीसीपी प्रारूप तैयारी के चरण के तहत है। जोखिम विश्लेषण रणनीति तैयार की गई है और इसे कार्यान्वित किया जाना है, लेकिन यह नियमों की अधिसूचना के बाद ही संभव है।

एक प्रतिनिधि द्वारा यह बताते हुए जीएम खाद्य का मुद्दा उठाया गया था कि लगभग 75 प्रतिशत प्रसंस्कृत खाद्य में, किसी न किसी रूप में जीएम खाद्य आधारित कच्ची– सामग्री निहित है। अध्यक्ष ने कहा कि जीएम खाद्य एफएसएस अधिनियम का हिस्सा है। हालांकि, अब सरकार द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के सभी मुद्दों से निपटने के लिए एक अलग नोडल एजेंसी का प्रस्ताव किया गया है। इसलिए एफएसएसएआई अधिनियम के इस विशेष प्रावधान को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

पूर्वोत्तर के प्रतिनिधि ने बताया कि हींग का पैकेट यह 'घटिया' था के विशिष्ट अंकन के साथ बेचा जा रहा था। यह भी संकेतित किया गया कि पैक उत्पादों में से कुछ पर कोई निशान/लोगो नहीं था। अध्यक्ष ने बताया कि पीएफए के पास पहले से ही कानून के इस तरह के उल्लंघन के लिए समाधान था क्योंकि इन्हें गलत ब्रांच वाले भोजन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और राज्यों के पास तदनुसार कार्रवाई करने के लिए अधिकार है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, एफएसएसएआई द्वारा सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक गांव में खाद्य सुरक्षा योजना होनी चाहिए जिसमें पीने योग्य पानी, निपटान योग्य बर्तनों का उपयोग, स्वच्छता के बारे में जागरूकता, अच्छी विनिर्माण प्रथाओं का उपयोग आदि निर्दिष्ट हों। अध्यक्ष, एफएसएसएआई ने आगे कहा कि अनुभव ने दर्शाया है कि एक राज्य की संरचना अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल नहीं हो सकती है। इसलिए, परामर्श की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। उल्लेख किया गया था कि कोलकाता में सड़क खाद्य व्यापार संचालकों के स्तर पर जागरूकता के प्रसार के पहलुओं को लागू किया गया था। ग्रामीण ऊर्जा समिति ऐसा ही एक उदाहरण था, जहां पंचायत स्तर शामिल थे।

फिक्की के प्रतिनिधि ने कहा कि संगठित क्षेत्रों में अधिनियम को लागू करना आसान है। हालांकि, जहां लोग एक असंगठित क्षेत्र में हैं वहां इसका कार्यान्वयन कठिन हो सकता है। सीईओ, एफएसएसएआई ने सुझाव दिया कि असंगठित क्षेत्रों में परिणाम प्राप्त करने के लिए आशा जैसे तंत्र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाद्य व्यापार संचालकों में कोडेक्स मार्गनिर्देशों के बारे में जागरूकता का मुद्दा उठाया गया था। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यह एफएसएसएआई के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर कार्य शुरू किया जा रहा है।

<u>कार्यसूची 6: आयातित खाद्य के लिए सुरक्षा प्रणाली:</u>

स्मार्ट गवर्नेंस के राष्ट्रीय संस्थान से श्री श्रीनिवासन (एनआईएसजी) ने आयातित खाद्य पदार्थों के लिए आईटी पर आधारित सुरक्षा प्रणाली के संचालन पर एक प्रस्तुति पेश की। यह एफएसएस अधिनियम, 2006 के 47 (5) की वैधानिक आवश्यकता के अनुसार एक प्रणाली विकसित करने का एक अभ्यास था। अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप में, पहले चरण में एफएसएसएआई द्वारा मौजूदा 5 बंदरगाहों पर आयात निकासी के लिए अधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति से इसे शुरू किया गया है। नमूने के त्वरित विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला की बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार करने के लिए, निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) प्रयोगशालाएं और एनएबीएल से मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को भी अधिकृत किया गया है। दूसरे चरण में जोखिम ढांचे के संचालन को शामिल

किया जाएगा। बाद में, कुछ बंदरगाहों और हवाई अड्डों सहित 12 और बंदरगाहों को शामिल किया जाएगा।

कार्यसूची 7: फूड रिकॉल प्रक्रिया पर मसौदा नियमन:

निदेशक (प्रवर्तन) ने फूड रिकॉल प्रक्रिया के मसौदा विनियम पर एक प्रस्तुति पेश की। इस विनियमन का उद्देश्य खाद्य व्यापार संचालकों को असुरक्षित भोजन की पहचान और इसे हटाने पर मार्गदर्शन करना है। रिकॉल प्रक्रिया की मजबूती से संबंधित मुद्दों और प्रावधान अपील से संबंधित मुद्दों को उठाया गया। चेन्नई के उपभोक्ता प्रतिनिधि, श्री देसीकन ने खाद्य पदार्थों के गलत नामकरण के बारे में चर्चा की। डॉ वासिरेड्डी ने कहा कि भोजन का पुनःपरिसंचरण विनाशकारी हो सकता है इसलिए असुरक्षित भोजन को नष्ट करने के लिए भी प्रावधान होना चाहिए।

फिक्की के श्री समीर के पास रिकॉल में बड़े और छोटे उल्लंघन के बारे में एक सुझाव था। उन्होंने अपील के प्रावधान की समय सीमा और उत्पादन की बहाली के बारे में भी सुझाव दिया। सुश्री केया घोष ने संकेतित किया कि खुले छोर की धाराएं नहीं भी हो सकती हैं इसलिए भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है ।

सीईओ द्वारा स्पष्ट किया गया था कि छोटे और बड़े दोनों उल्लंघनों को रिकॉल प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि वह फूड रिकॉल प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले, अपील प्रावधानों के मुद्दे पर आगे के सुझावों का स्वागत करेंगे।

कार्यसूची 8: राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सूचना अद्यतन प्रणाली

लॉजिकसॉफ्ट के श्री नाथन ने राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जानकारी अद्यतन प्रणाली पर एक प्रस्तुति पेश की। उन्होंने कहा कि इसआईटी आधारित प्रणाली से केंद्र और राज्यों के बीच सूचना की उपलब्धता की सुविधा होगी। खाद्य सुरक्षा आयुक्त जानकारी को अपलोड कर सकते हैं। यह एक एकीकृत सूचना प्रणाली है और यह एफएसएसएआई वेबसाइट का हिस्सा है

कार्यसूची 9: पंजीकृत चिकित्सा पेशेवरों द्वारा विषाक्त भोजन की घटनाओं की रिपोर्टिंग

सीईओ ने जानकारी दी कि एफएसएस अधिनियम की धारा 35 को अधिसूचित किया गया है। संबंधित अधिकारी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों में उनकी जानकारी में आने वाली विषाक्त भोजन की सभी घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरएमपी द्वारा ऐसी रिपोर्टिंग भोजन निगरानी का अनिवार्य हिस्सा है। सीईओ ने इस पर बल दिया कि यह रिपोर्टिंग तंत्र रणनीतियों के लिए भविष्य की योजना बनाने हेतु महत्वपूर्ण है।

कार्यसूची 10: राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों से पीएफए कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित लंबित सूचना

अधिकांश राज्यों ने वर्ष 2009 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, हालांकि, पंजाब, दादरा और नागर हवेली, जम्मू–कश्मीर, मणिपुर, उड़ीसा और लक्षद्वीप के राज्यों ने ऐसा नहीं किया है और उनसे अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। सभी राज्यों से दो महीने के भीतर वर्ष 2010 के लिए पीएफए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। सीईओ, एफएसएसएआई ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम और राजस्थान जैसे राज्यों की सराहना की, जो वर्ष 2010

के लिए पहले ही अपनी रिपोर्ट भेज चुके हैं। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से संसदीय आश्वासन लंबित थे। उनसे भी इसमे तेजी लाने का अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यसूची मदों पर विचार–विमर्श किया गया.

कार्यसूची 11(ए): मादक पेयों का नियमन

सीईओ, एफएसएसएआई द्वारा सूचित किया गया कि चूंकि शराब को खाद्य के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए मसौदा नियमों को विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही वह मूल्यांकन के लिए तैयार हो जाएगा। सीएसी ने फैसला किया कि मादक पेयों पर नियमों की अधिसूचना की जा सकती है।

कार्यसूची 11(बी): सड़क भोजन और भोजनालय सहित भारत में 'खाद्य उद्योग' पर बेसलाइन सर्वे

यह निर्णय लिया गया कि गांव स्तर तक सड़क विक्रेताओं सहित सभी खाद्य व्यापार संचालकों के लिए सर्वेक्षण करने की जरूरत है। यह आकलन और खाद्य व्यापार संचालकों पर एक डेटाबेस के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। यह डेटा कर्मचारियों, प्रयोगशालाओं, स्थान जैसी बुनियादी सुविधाओं आदि के प्रक्षेपण के लिए किसी भी प्रकार की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। सदस्यों ने सुझाव दिया कि इस उद्देश्य के लिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या किसी अन्य संस्थान से संपर्क किया जा सकता है। इसके बाद एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जा सकता है।

कार्य सूची 11(सी): राज्य स्तर पर सलाहकार पैनल का गठन

एक सुझाव था कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्य स्तर पर अलग सलाहकार पैनल गठित किया जा सकता है। सलाहकार पैनलों को आवश्यक माना गया क्योंकि प्रत्येक राज्य की कुछ राज्य विशिष्ट समस्याएं और मुद्दे होते हैं। इसके विपरीत विचार भी व्यक्त किए गए जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर पैनल और समितियां मौजूद है, इसलिए राज्य स्तरीय सलाहकार पैनल की नीतियां तैयार करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी। इसके अलावा, चूंकि कार्यान्वयन में एकरूपता का होना आवश्यक है और राष्ट्रीय स्तर समितियों / पैनलों में पर्याप्त क्षेत्रीय और वैज्ञानिक प्रतिनिधित्व है, इसलिए सलाहकार पैनल ज्यादा योगदान करने में सक्षम नहीं होंगे।

कार्यसूची 11(डी): नागरिक चार्टर

सीईओ ने नागरिक चार्टर विषय को प्रस्तुत किया और कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और सभी हितधारकों के लिए एफएसएसएआई रणनीतियों और जनादेश के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही दर्शाते हैं और इसलिए इनका व्यापक और सरल होना जरूरी है। यह भी सूचित किया गया कि मसौदा नागरिक चार्टर एफएसएसएआई वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और सभी हितधारकों के सुझावों का स्वागत है। राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसकी विशेष रूप से जांच करने की जरूरत है क्योंकि यह राज्य,/केंद्र शासित प्रदेशों से भी संबंधित होगा।

कार्यसूची 11(इ): व्हिसल ब्लोअरयोजना

सीईओ ने जानकारी दी कि सरकार द्वारा एक व्हिसल ब्लोअर योजना घोषित की गई है। योजना में हितधारकों के बीच एक ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना शामिल है जो प्राधिकरण को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए तैयार होगा। इस तरह की जानकारी पर आगे की

कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। एक कॉल सेंटर/शिकायत निपटान तंत्र इस बात का जवाब हो सकता है।

अपने समापन भाषण में, सीईओ, एफएसएसएआई ने सभी प्रतिभागियों को चर्चा में उनकी सक्रिय भागीदारी और बहुमूल्य सुझाव प्रदान करने के लिए, जो एफएसएसएआई के कार्यक्रमों और नीतियों को और परिष्कृत करने में मददगार होगा, धन्यवाद दिया.

केंद्रीय सलाहकार समिति की सिफारिशें:

तीसरी सीएसी की सिफारिशों कोनिम्न रूप में संक्षिप्त किया गया है:

1. सभी राज्यों ने एफएसएसएआई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तैयार होने पर सहमति व्यक्त की। नियम को अधिसूचित करने के बाद उन्हें तीन महीने का समय दिया जा सकता है जिसके दौरान वे कानून के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को अधिसूचित करने की कार्रवाई करेंगे। इस दौरान कर्मियों, बुनियादी सुविधाओं, आदि की आवश्यकताओं के बारे में सभी आवश्यक तैयारी शुरू की जाएगी।

2. प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और एफएसएसएआई की सहायता के लिए योजना आयोग से बुनियादी ढांचे खासकर प्रयोगशालाओं का निर्माण करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा सकती है।

3. यह निर्णय लिया गया कि एफएसएसएआई एनएबीएल मान्यता प्रक्रियाओं पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं का संचालन करने के लिए क्यूसीआई और एनएबीएल से संपर्क कर सकता है ताकि जिन प्रयोगशालाओं को उन्नत किया जाना है उन्हें प्रक्रिया के दौरान अड़चनों का सामना न करना पड़े।

4. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित डेटा अद्यतन प्रणाली से केंद्र और राज्यों के बीच विचारों के आदान–प्रदान और संचार में सुधार करने में मदद मिलेगी इसलिए इस सकारात्मक गतिविधि को कार्यान्वित और आगे ले जाया जाना चाहिए। सभी प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इस जानकारी अद्यतन प्रणाली का पूरी तरह से उपयोग करेंगे इसके लिए लॉगिन पासवर्ड प्रदान किया जा सकता है।

5. सिद्धांत रूप में सहमति व्यक्त की गई कि हर राज्य में एक नियंत्रण कक्ष हो सकता है जो आम आदमी की पहुँच का हो। एक राष्ट्रीय स्तर हेल्पलाइन प्रणाली उपभोक्ताओं और खाद्य व्यापार संचालकों दोनों के लिए अच्छी होगी और शिकायत से निपटने के तंत्र के रूप में अतिरिक्त उपकरण का काम करेगी। इस सहायता लाइन को अनुवर्ती कार्रवाईयों के लिए राज्य नियंत्रित संसाधनों से जोड़ा जा सकता है।

6. खाद्य व्यापार पर एक डेटा बेस विकसित करने के लिए एफएसएसएआई द्वाराभारतीय सांख्यिकी संस्थान जैसी संस्थाओं की मदद से एक सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा ताकि देश में खाद्य व्यापार संचालकों की स्थिति की सटीक मात्रा, आकार, प्रकार, पंजीकरण आदि के संबंध में अनुमान लगाया जा सके।

7. यह स्वीकार किया गया कि व्हिसल ब्लोअर योजना शासन में पारदर्शिता बनाने और खुफिया जानकारी जुटाने को प्रोत्साहित करने में मददगार होगी। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक राज्य द्वारा इनाम के प्रावधानों के साथ एक औपचारिक योजना तैयार की जाएगी।

8. राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मसौदा नागरिक चार्टर में सुधार के लिए सुझाव भेजे जा सकते हैं।

अनुलग्नक–1

प्रतिभागियों की सूची

1. डॉ के. सदाशिवम, जेडी, डीपीएचआरएम, चेन्नई, तमिलनाडु
2. डॉ यू. के. साहू, निदेशक, जन स्वास्थ्य, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
3. श्री सलीम ए वेलजी, निदेशक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, गोवा
4. श्री एस. के. नंदा, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, जीएनसीटी, दिल्ली
5. श्री लाल सवमा, नोडल अधिकारी (पीएफए), डीएचएस, मिजोरम
6. श्री बीसी जोशी, उपायुक्त, खाद्य और पीडी, नई दिल्ली
7. श्री ए के जैन, निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली।
8. श्री श्रीनिवास जे., एनआईएसजी, हैदराबाद
9. श्री अरविंद कुमार आईएएस, निदेशक नीति, खाद्य एवं पीडी विभाग, नई दिल्ली।
10. श्री आर. के. वत्स, आयुक्त, एफएसएस, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
11. डॉ दिलबाग सिंह आईएएस, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तराखंड
12. श्री के. अनिल कुमार, संयुक्त आयुक्त, खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम, केरल
13. श्री डी एन नाईक, आयुक्त, कर्नाटक
14. श्री एस. के. शर्मा, अपर आयुक्त, डीएडीएफ, कृषि मंत्रालय
15. श्रीमती सीमा व्यास, एफडीए, मुंबई, महाराष्ट्र
16. श्री विनोद करले आईएएस, संयुक्त निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, चंडीगढ़ (संघ शा. प्र.)
17. श्री एन आर गुरुंग, लोक विश्लेषक, सिक्किम
18. डॉ. केया घोष सीयूटीएस, कोलकाता
19. डॉ एससी खुराना, डीएमआई, डीएसी, कृषि मंत्रालय, फरीदाबाद
20. डॉ श्रीनिवास गौड़ा, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बंगलौर, कर्नाटक
21. श्री ए. के. ओझा, सहायक निदेशक, एमएसएमई, निर्माण भवन, नई दिल्ली
22. श्री समीर बरडे, एएससीए, फिक्की
23. डॉ सी. लालथानमाविया, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, मिजोरम

24. डॉ दीपिका चन्हा, उपायुक्त, गांधीनगर, गुजरात

25. डॉ श्रीमती सुचरिता मूर्ति, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

26. श्री प्रदीप चोर्डिया, चोर्डिया फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, पुणे।

27. डॉ एस. पी. वसीरेड्डी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, विमका बैब्स, हैदराबाद।

28. श्री एल. हाओकिप, अवर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली,

29. श्री टेचाम ब्रोजेंद्रो खाबा, उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मणिपुर

30. श्री एसके नंदी, संयुक्त आवासीय आयुक्त–त्रिपुरा राज्य, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली

31. डॉ के. वी. माथेकर, एफडीए, महाराष्ट्र

32. श्री आर. देशीकन, न्यासी, कन्सर्ट, तमिलनाडु

33. डॉ के. बी. सूद, उप निदेशक स्वास्थ्य, द्वारा डीएचएसआर एसडीए, शिमला, हिमाचल प्रदेश

34. डॉ दिलीप के. बाहगे खाद्य आयुक्त, पांडिचेरी

35. श्री एच.आर. शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त, एफडीए, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

36. श्रीमती कुमकुम मारवाह, संयुक्त तकनीकी सलाहकार, खाद्य एवं पोषण बोर्ड, एम/ओ डब्ल्यूसीडी, नई दिल्ली

37. श्री डी.के. दुबे, एफआई, मध्य प्रदेश

38. श्री अभिषेक बिहारी गौड़, एफआई, सतना, मध्यप्रदेश

39. श्री सतीश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर

40, आयोनेर खाद्य सुरक्षा, जम्मू व कश्मीर

41. डॉ जे. एस. कल्हण, उप–निदेशक, सीएचडी, लुधियाना, पंजाब

42. श्री के. सुब्रमण्यम, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, छत्तीसगढ़

43. श्री पी.सी. मसंद, 59, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली

44. श्री अनूप मित्तल, डीन, केआईआईटी विश्वविद्यालय